सत्यमेव जयते

# लोक प्रशासन में प्राथमिकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

# Prime Minister's Awards for Excellence in Implementation of Priority Programmes

*योगः कर्मसु कौशलम्*

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms & Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

# प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ विद्यालय और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार

10वाँ सिविल सेवा दिवस, 2016

20–21 अप्रैल, 2016

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

# Prime Minister's Awards for Excellence in Implementing Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Swachh Bharat Mission (Gramin), Swachh Vidyalaya and Soil Health Card Programmes

10th Civil Services Day, 2016
20-21 April, 2016

Department of Administrative Reforms & Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

# विषय–सूची


| प्राथमिकता कार्यक्रमों में पुरस्कार | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** | | |
| **राज्यों का समूह** | **जिला** | |
| (i) अन्य राज्य | उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल | 3 |
| (ii) पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य | नगाँव, असम | 5 |
| (iii) संघ राज्य क्षेत्र | चंडीगढ़ | 8 |
| **2. स्वच्छ भारत (ग्रामीण)** | | |
| (i) अन्य राज्य | बीकानेर, राजस्थान | 12 |
| (ii) पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य | पश्चिम सिक्किम सिक्किम | 16 |
| **3. स्वच्छ विद्यालय** | | |
| (i) अन्य राज्य | अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश | 19 |
| (ii) पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य | अनंतनाग, जम्मू व कश्मीर | 21 |
| (iii) संघ राज्य क्षेत्र | दादरा एवं नागर हवेली | 23 |
| **4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम** | | |
| (i) अन्य राज्य | बलरामपुर, छत्तीसगढ़ | 27 |
| (ii) पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य | हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश | 31 |


# Contents


| *Awards in the Priority Programmes* | | *Page No.* |
|---|---|---|
| **1. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)** | | |
| **Group of States** | **District** | |
| (i) Other States | North 24 Parganas, West Bengal | 3 |
| (ii) North East & Hill States | Nagaon, Assam | 5 |
| (iii) Union Territories | Chandigarh | 8 |
| **2. Swachh Bharat Mission (Gramin)** | | |
| (i) Other States | Bikaner, Rajasthan | 12 |
| (ii) North East & Hill States | West Sikkim, Sikkim | 16 |
| **3. Swachh Vidyalaya** | | |
| (i) Other States | Ananthapuramu, Andhra Pradesh | 19 |
| (ii) North East & Hill States | Anantnag, Jammu & Kashmir | 21 |
| (iii) Union Territories | Dadra and Nagar Haveli | 23 |
| **4. Soil Health Card Scheme** | | |
| (i) Other States | Balrampur, Chhattisgarh | 27 |
| (ii) North East & Hill States | Hamirpur, Himachal Pradesh | 31 |

प्रधानमंत्री
जन धन
योजना



PRADHAN MANTRI
JAN DHAN
YOJANA

# स्कीम का सार

**प्रधानमंत्री जन धन योजना** वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है जिसका लक्ष्य वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः बैंक बचत और जमा खाता, धन प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है । इस वित्तीय समावेशन अभियान की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पहले संबोधन में की थी । यह स्कीम शीघ्र ही 28 अगस्त, 2014 के बाद शुरू की गई ।

इस स्कीम के शुभारंभ दिवस के अवसर पर 1.5 करोड़ (15 मिलियन) बैंक खाते खोले गए । गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड ने इस उपलब्धि को विश्व में कहीं भी अब तक एक सप्ताह में सर्वाधिक खोले गए बैंक खातों के रूप में दर्ज किया है । गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड ने यह घोषणा की है कि "वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में एक सप्ताह में खोले गए बैंक खातों की अधिकतम संख्या 18,096,130 है तथा इस लक्ष्य को भारत के बैंकों द्वारा 23 से 29 अगस्त, 2014 तक प्राप्त किया।" 10 फरवरी, 2016 तक 20 करोड़ (200 मिलियन) से अधिक बैंक खाते खोले गए तथा इस स्कीम के अंतर्गत रु. 323.78 बिलियन ($ 4.80 बिलियन अमेरिकी डालर) जमा किए गए ।



# Brief of the Scheme

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) is the National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, namely Bank Savings & Deposit Accounts, Remittances, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner. This Financial Inclusion campaign was announced by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, in his first Independence Day speech of 15 August, 2014. The Scheme was launched soon after, on 28 August, 2014.

On the inauguration day of the Scheme, 1.5 crore (15 million) bank accounts were opened. The Guinness World Records recognizes this achievement as the largest opening of Bank Accounts ever made in a single week anywhere in the world ever. The Guinness World Records Certificate declares "The most bank accounts opened in one week as a part of financial inclusion campaign is 18,096,130 and was achieved by banks in India from 23 to 29 August, 2014". By 10 February, 2016, over 20 crore (200 million) bank accounts were opened and Rs.323.78 billion (US$4.80 billion) were deposited under the scheme.

# समूह – अन्य राज्य
# श्रेष्ठ जिला – उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल

## 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में इस जिले में अपनाई गई सबसे महत्वपूर्ण कार्यनीति यह थी कि अन्य सरकारी विभागों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, कृषि, मनरेगा (एमजीएनआरईजीए), लघु उद्योग, एसएचजी आदि के साथ अभिसरण (कन्वर्जेंस) करना था ।

सभी संसाधनों विशेषकर इन विभागों के कार्मिकों का लाभ लेने और अनुकूलन करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया गया था। इस जिले के सभी 22 प्रखंडों के ब्लॉक स्तर बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठक आयोजित की गई और संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत किया गया । संबंधित ब्लॉक के सभी शाखा प्रबंधकों, ब्लॉक स्तर सरकारी अधिकारियों, पंचायत प्राधिकारियों, स्वयं सहायता समूह के ग्राम पंचायत विशेषज्ञ व्यक्तियों (जीपीआरपी) ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु बैंकों द्वारा एक हजार से ज्यादा बैंकिंग अभिकर्ता (बीसी) नियुक्त किए गए । सभी बैंकों द्वारा रु. 5000.00 मासिक वेतन रखा गया । साथ ही बैंकों ने सभी बैंकिंग अभिकर्ता (बीसी) को नया बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडी) खोलने के लिए मासिक वेतन के अतिरिक्त कमीशन भी दिया । सभी बैंकिंग अभिकर्ताओं को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफार्म पर ऑनलाइन लेन–देन के लिए लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया गया। अब सभी बीसी को स्थिर कीओस्क में परिवर्तित कर दिया गया ।

सभी बैंकों ने नया खाता और लेन–देन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कार देने की भी घोषणा की । मिशन अवधि के दौरान बैंक रहित ग्रामीण उप सेवा क्षेत्र (एसएसए)/जीपी अथवा शहरी वार्ड में 40 बैंक शाखाएं खोली गई ।

बैंक खाता खोलने के लिए दिनांक 20.08.2014 को विभिन्न स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया । शुभारंभ दिवस पर अग्रणी बैंक द्वारा खाता खोलने के लिए मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जहां 27 भागीदार बैंकों ने खाते खोलने के लिए अपने स्टॉल लगाए।

जिले के सभी बैंक शाखाओं ने शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खाता खोलने के लिए शिविर का आयोजन किया ।

व्यापक मॉनीटरिंग प्रणाली विकसित की गई थी । अग्रणी जिलों के दैनिक मिथ्या रिपोर्ट ट्रैकर की शुरूआत की गई । अल्पावधि में ही बैंकों द्वारा सभी 603 ग्रामीण एसएसए और 711 शहरी वार्ड में एक परिवार में कम से कम एक खाता खोला गया तथा 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया ।



# Group – Other States
# Best-performing – District-North 24 Parganas, West Bengal

## 1. Exemplary Work done in District under the Scheme

The most significant strategy adopted for implementation of the PMJDY programme in the district was that of convergence with other government departments such as Education, Health, Election, Agriculture, MNREGA, Small Scale Industries, SHGs, etc.

A detailed survey was undertaken, leveraging and optimizing all resources especially personnel from these departments. Block level Bankers Committee (BLBC) meetings of all 22 Blocks of the district were organized and the officials concerned were sensitized. All the Branch Managers in the Blocks, Block-level Govt. Officers, Panchayat authorities, Gram Panchayat Resource Persons (GPRPs) of Self Help Groups worked shoulder-to-shoulder.

More than one thousand Banking Correspondents (BCs) were appointed by the banks for implementation of the Scheme. Monthly salary @Rs.5000.00 was introduced by all banks. Banks paid commission to all BCs for opening of new Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts, in addition to the monthly salary. All the BCs were provided with laptop and internet connectivity for online transactions on Core Banking Solution (CBS) platform. All BCs have now been converted into fixed point kiosks.

All banks have also announced reward for best performance in opening of new accounts and transactions. During the mission period, 40 bank branches were opened in unbanked rural Sub Service Area (SSA) / GP or urban wards.

Account opening camps were organized at different levels on 20.08.2014. A mega account opening camp was organized by the lead bank on the launching day, where all 27 participating banks set up their account opening stalls.

All bank branches of the district hold the camps for opening of accounts on every Saturday from morning 8 am to evening 8 pm.

Extensive monitoring system was developed. Daily false report tracker of the Lead District was introduced. Within a short period, 100% financial inclusion was achieved, with at least one account per household having been opened by banks in all the 603 rural SSAs and 711 urban wards.

## 2. आम नागरिकों के लिए लाभ

अब मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत मजदूरी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बैंक खातों का प्रयोग एलपीजी सब्सिडी का सीधा अंतरण, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कन्याश्री प्रकल्प के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भी किया जा रहा है जिसमें 2,07,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए ।

सभी पीएमजेडीवाई के खाता धारक को रुपे डेबिड कार्ड से संबद्ध रु.1.00 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया गया है । इसी प्रकार दिनांक 14.08.2014 से 26.01.2015 के बीच पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खाता खोलने वाले खाता धारक को रु. 30000/– का मुफ्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

जिला प्रशासन ने अगस्त, 2015 के दौरान बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल में हुए क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का वितरण भी किया । लगभग 2,65,000 किसानों ने क्षतिपूर्ति प्राप्त की तथा इन्हें प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक खातों के माध्यम से लगभग रु. 108.00 करोड़ क्षतिपूर्ति का वितरण किया गया ।

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

बैंक मित्रों द्वारा संचालित उपभोक्ता सेवा एकक (सीएसपी) के माध्यम से ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सभी बैंक खाताधारकों को द्वार पर ही बैंकिंग सुविधा का लाभ प्रदान किया गया ।

सरकार प्रायोजित स्कीमों में वित्तीय लेन–देन में सटीकता और निपुणता में काफी सुधार हुआ है । फलस्वरूप विभिन्न सरकारी स्कीम में वित्तीय भ्रष्टाचार के स्तर में कमी आई है ।

अब कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहे लोग बिचौलिए, स्थानीय ऋणदाताओं और धोखाधड़ी करने वाले चिट फंड संगठनों से मुक्त हुए हैं ।

आधार कार्ड नामांकन और मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) कार्ड धारकों को प्रणाली में दर्ज कराने की संख्या में व्यापक रूप से सुधार हुआ है । डीबीटी कवरेज में वृद्धि हुई। स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने बेहतर क्रेडिट रेश्यों प्राप्त किया ।

कन्याश्री नामांकन स्कीम के अंतर्गत भी सीधे ही बैंक खाता में निधि का सफलतापूर्वक अंतरण किया गया ।

इसी प्रकार युवाश्री, शिक्षाश्री जैसी स्कीमों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ जिससे प्रभावी और कुशल शैक्षणिक लाभ उपलब्ध हुए ।

बैंक खाता खुलने के कारण मांग में वृद्धि होने से नए किओस्क के जरिए बैंक सुविधा रहित ग्राम पंचायतों को बेहतर कवरेज प्राप्त हुआ।



## 2. Benefit to the Common Citizens

Wages under MGNREGA are now being directly deposited in the beneficiaries' account. Further, bank accounts are being used for Direct Benefits Transfer of LPG subsidy, widow pensions, old age pensions and also scholarships to students under Kanyashree Prakalpa, in which 2,07,000 students benefitted.

Accident insurance coverage of Rs.1.00 lakh has been extended to all PMJDY a/c holders, with free of cost, linked with RuPay debit card. Similarly, coverage of life insurance of Rs.30,000/- has been given free of cost for all PMJDY account holders who opened accounts between 14.08.2014 to 26.01.2015.

Also, the District administration distributed during August 2015, compensation against crop damage to the flood affected farmers. Approximately 2,65,000 farmers got the compensation and about Rs.108 crore was distributed through the PMJDY bank accounts.

## 3. Impact of the Scheme in District

Door-step banking was provided to all bank account holders in rural and semi urban areas through Customer Service Points (CSP) operated by Bank Mitras.

Accuracy and efficiency in financial transactions has greatly improved in government sponsored schemes. As a result, corruption levels in various government schemes have reduced.

People living in difficult geographical areas have now been freed from middlemen and local money lenders as well as fraudulent chit fund organizations.

Aadhaar card enrollment and seeding of MGNREGA card holders with Aadhaar improved considerably. DBT coverage increased. SHG members received better credit.

Under the Kanyashree scheme too, funds were successfully transferred into bank accounts, directly.

Similarly, performance of such schemes as Yuvashree, Shiksha Shree improved, thereby providing educational benefits more efficiently and effectively.

There was better coverage of unbanked Gram Panchayats through new kiosks since demand increased due to opening of bank accounts.

# समूह – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य
# श्रेष्ठ जिला – नगाँव, असम

## 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कुल **4,27,456** बैंक खाते खोले गए । जिले में संबद्ध बीमा स्कीमों का कवरेज भी बहुत उच्च है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1,00,301 परिवारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 4094 परिवारों को कवर किया गया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के आरंभ से कुल **2,23,979 रुपे कार्ड** वितरित किए गए हैं ।

पूरे जिले में कुल **133 वित्तीय साक्षरता/जागरुकता शिविर** आयोजित किए गए जिनमें **अल्प सुविधा वाले** क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया । (दूर दराज बसी आबादी जिनके **5–10** कि.मी. की परिधि के अंदर कोई बैंक शाखा नहीं है)

**कुल 360 बैंक मित्र** सभी मौजूदा अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों की मांग को पूरा कर रहे हैं । संबद्ध बैंक शाखाओं द्वारा उन्हें उपकरण का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

वित्तीय साक्षरता शिविरों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए **माता समूह,** स्वयं सहायता समूह और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों को स्थानीय बैंक शाखाओं से जोड़ा गया ।

**विशेष जिला स्तर कार्यान्वयन समिति** में उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), परियोजना निदेशक (डीआरडीए) और नाबार्ड के प्रतिनिधि तथा अन्य बैंक सदस्य हैं जो अभिसारिता (***कन्वर्जेंस***) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों के कार्यकलापों का विभिन्न संबंधित विभागों के साथ समन्वय करती है । जिला स्तर समन्वय समिति सभी बैंकों के कार्य निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा करती है ।

एक जिला शिकायत निवारण कॉल सेंटर [1077 (निःशुल्क) और 03672–236827] का भी गठन किया गया ताकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके ।

जिले के अति संवेदनशील जगहों की पहचान की गई तथा इन क्षेत्रों में **9 व्यापक वित्तीय जागरूकता शिविर** आयोजित किए गए ।

**सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलाप** जैसे कि **नुक्कड़ नाटक, लघु चलचित्र,** सूचना–पत्र, पैम्फलेट आदि को वितरण करने और घर–घर जाने का अभियान आयोजित किया गया ।

बैंक खाता खोलने के लिए सरलीकृत केवाईसी के भाग के रूप में गांवों में **गांव बुरहा** (ग्राम मुखिया) द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों को बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकार किया गया है।

**किसान क्लबों** को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए शामिल किया गया । इसके लिए **रूपे केसीसी जागरूकता शिविर** आयोजित किए गए ।



# Group – North East & Hill States
# Best-performing – District-Nagaon, Assam

## 1. Exemplary Work done in the District under the Scheme

A total of **4,27,456** bank accounts were opened under the PMJDY. The coverage of allied insurance schemes in the district achieved was also high. Thus, 1,00,301 households were covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and 4094 households were covered by the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).

A total of **2,23,979 RuPay Cards** were distributed since the launch of the PMJDY.

Total of **133 Financial Literacy/ Awareness Camps** were held across the district, with special focus on **shadow areas** (remote habitations without any bank branches within a radius of 5-10 km).

**A total number of 360 Bank Mitras** catered to all the existing shadow areas. Training on device use was imparted to them by the associated bank branches.

**Mothers Groups,** Self Help Groups and Panchayati Raj Institute members were roped in with the base bank branches to increase the community participation in financial literacy camps.

**Special District Level Implementation Committee** comprising Deputy Commissioner, CEO (Zilla Parishad), Project Director (DRDA) and representatives of NABARD as well as other banks coordinated the activities of banks with that of various Line departments to achieve ***convergence***. The District Level Coordination Committee reviews the performance of all the banks on a monthly basis.

A district grievance redress call centre [1077 (toll-free) and 03672-236827] was also set-up to facilitate the various processes under PMJDY.

The most vulnerable pockets in the district were identified and **9 intensive financial awareness camps** were conducted in these areas.

**Information Education and Communication (IEC) activities** such as ***street plays, short movies***, leaflet and pamphlet distribution as well as house-to-house campaigns were organized.

**Gaon Burahs** in the villages issued certificates which were accepted by bank branches for opening bank accounts as a part of simplified KYC.

**Farmers Clubs** were involved to disseminate information on RuPay Kisan Credit Card (KCC). **RuPay KCC awareness camps** were held for the same.

## 2. आम नागरिकों को लाभ

खाता धारक सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के अंतर्गत सीधे ही अपने बैंक खातों में परवर्ती और समानांतर धन अंतरण द्वारा लाभान्वित हुए यथा भारत सरकार के संबंधित विभागों द्वारा रसोई गैस सब्सिडी की पहल सुविधा, मनरेगा भुगतान आदि ।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा समूहों और गांव स्तर पर विद्यमान संस्थागत तंत्र जैसे कि एकीकृत बाल विकास विकास स्कीम (आईसीडीएस) के अंतंगत माता समूह, चाय बागों में बागान बाजार और ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों का भी प्रयोग किया गया जिसमें आम नागरिकों तक लाभों की पहुंच में व्यापक वृद्धि हुई।

राज्य स्कीमों जैसे कि मामोनी, माजोनी, नावाउ, बैडेउ, नबोवारी आदि जिनके प्रमुख लाभार्थी महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक हैं, के लाभ को भी सीधे बैंक खाते में अंतरित किया गया ।

ओवर ड्राफ्ट के रूप में **31.45 करोड़ रु.** की राशि निर्मुक्त की गई है जो बैंकों के जरूरतमंदों की सहायता हेतु आगे आने का एक सराहनीय प्रतिबिम्ब है । जारी किए गए कुल ओवर ड्राफ्ट में 50% छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किए गए हैं ।

स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2015–16 के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय (प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना–38894) और राज्य (मामोनी – 40958 और माजोनी – 2749) स्कीमों के अंतर्गत कुल **82,601** आदाता खाता चैक जारी किए ।

वर्ष 2015–16 में असम सरकार की वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल की स्कीम के अंतर्गत **10,776** लाभार्थियों के बैंक खातों में **21,55,200**/– रु. की राशि जमा की गई ।

राज्य सरकार की नाबाउ, बैडेउ और नबोवारी स्कीमों के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में कुल **8447** महिला लाभार्थियों ने सीधे अपने बैंक खातों में **8,44,70,000**/– रु. की धनराशि का लाभ प्राप्त किया ।



## 2. Benefits to the Common Citizens

The account holders benefitted by the subsequent and parallel money transfers, under the Direct Benefit Transfers (DBT) mechanism, to their bank accounts directly such as PAHAL benefits of cooking gas subsidies, MNREGA payments etc. by the Government of India departments concerned.

Existing institutional mechanisms present at village level such as Mothers Groups under Integrated Child Development Services, Bagan Bazars in tea gardens and Village Health Camps were utilized for furthering financial inclusion which substantially increased the reach of benefits to the common citizen.

Benefits of State schemes such as Mamoni, Majoni, Nabau, Baidew, Na-bowari etc. whose major beneficiaries are women and senior citizens, were also directly credited to bank accounts.

An amount of **Rs. 31.45 crore** has been issued as overdrafts, which is a commendable reflection of the banks coming to the aid of the needy. Out of the total overdrafts issued, 50% have been given to small and marginal farmers.

Health Department has issued a total of **82,601** account payee cheques in the year 2015-16 under various Central (PM Janani Suraksha Yojana - 38894) and State (Mamoni – 40958 and Majoni - 2749) schemes.

An amount of **Rs. 21,55,200** was credited to the bank accounts of **10,776** beneficiaries under Health Care for the Aged Scheme of the state government in the year 2015-16.

A total of **8447** women beneficiaries received their benefits amounting to **Rs. 8,44,70,000** credited directly into their bank accounts in the last financial year, under Nabau, Baidew and Nabowari Schemes of the state government.

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

प्रधानमंत्री जन धन योजना से पूर्व, नगांव में केवल 2,79,349 बैंक खाते थे । स्कीम के आरंभ के पश्चात कुल **4,27,456** बैंक खाते खोले गए ।

जिले में संबद्ध बीमा स्कीमों का कवरेज भी बहुत उच्च है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत **1,00,301** परिवारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत **4094** परिवारों को कवर किया गया है।

पूर्व में जिले की कुल आबादी के 10% से कम की आबादी को बैंकिंग सेवाओं से कवर किया गया था। अब जिले में पूर्णतः कवरेज की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है और प्रत्येक परिवार का कम से कम एक बैंक खाता है ।

अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी इस स्कीम का एक प्रमुख प्रभाव है । पूर्व के बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों को अब बैंक मित्रों के जरिए बैंकिंग सेवाओं से कवर किया गया है ।

बैंक मित्रों के माध्यम से दैनिक लेन–देन में भी व्यापक तौर पर वृद्धि हुई है जिसके अधिकांश भाग में परिवारों की नियमित बचत शामिल है ।

चाय बागान के कामगारों सहित लोगों के विभिन्न समूहों के बीच बचत करने की आदत का विकास हुआ है। अब चाय बागान कामगार जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, का साप्ताहिक वेतन सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है जिससे उनकी बचत क्षमता में वृद्धि हो रही है।

इससे बैंक ऋणों की आसानी से उपलब्धता के कारण लघु उद्योग उपक्रमों की स्थापना की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। अनेक दैनिक श्रमिकों ने स्व–रोजगार शुरू किया है जिसने उन्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है ।

इससे उत्पादक कार्यकलापों को अत्यधिक बल मिला है। परिणामस्वरूप महिलाएं जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं भी शामिल हैं, का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है ।



## 3. Impact of the Scheme in the District

Prior to PMJDY, there were only 2,79,349 bank accounts in Nagaon. After the onset of the Scheme, a total of **4,27,456** accounts were opened.

Achievement of coverage of allied insurance schemes in the district is also high. **1,00,301** households were covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and **4094** households were covered by Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).

Earlier, less than 10% of total population of the district was covered by banking services. Now, the district has cent percent coverage and every household has at least one bank account.

A significant reduction in shadow areas has been a major impact of the Scheme. Previously unbanked pockets are now covered under banking services through Bank Mitras.

The daily transactions though Bank Mitras have also increased substantially, a major chunk of which comprises regular savings of households.

Savings habit has developed amongst the various groups of people, including the tea garden workers. Now, the weekly salaries of tea garden workers, majority of whom are women, are credited directly into their bank accounts, further enhancing their savings capacity.

There has also been a huge increase in small scale enterprises being established owing to the easy access to bank loans. Several daily wage laborers have now taken up self-employment, which has made them independent and self-reliant.

There is a huge thrust on productive activities. As a result, women, including those from minority communities, have become economically empowered.

## समूह – संघ राज्य क्षेत्र
## श्रेष्ठ कार्य निष्पादन जिला – चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र

### 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दो लाख बीस हजार से अधिक बैंक खाता खोले गए । लगभग 1,82,000 जारी किए गए रुपे कार्ड में से एक लाख से अधिक कार्डों को सक्रिय किया गया । 1,60,000 से अधिक खाता धारकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कुल 59 करोड़ रुपये जमा किए ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए 1,99,196 खातों में आधार संख्या दर्ज कराई गई । छात्रों को उनके खातों में छात्रवृत्ति देने के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का उपयोग किया जाता है । सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण करने के लिए आधार सक्षम बायो मीट्रिक भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है । एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार आधारित एलपीजी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) भी प्रचलन में है।

रुपे कार्ड को सक्रिय करने और वितरण करने हेतु लगभग 50 शिविर आयोजित किए गए । एफएम रेडियो, समाचार–पत्रों, पैम्फलेट, परामर्श, प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से जनसमूह को लक्षित करके जागरूकता उत्पन्न की गई ।

भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक मित्रों की नियुक्ति की और चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक 25 सक्रिय बैंक मित्र स्थापित किए गए । बैंक मित्रों द्वारा पिछले तीन माह में रु. 30.28 करोड़ के 40,615 लेन–देन किए गए । सभी बैंकों के लिए जमा और आहरण करने हेतु बैंक मित्रों द्वारा 16 माइक्रो एटीएम का उपयोग किया जाता है ।

शेष बचे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर सर्वेक्षण किया गया । लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए संपर्क केंद्र (सीएससी) का लाभ लिया गया ।

इस पहल की सफलता के लिए ग्राम सरपंच जैसे सामाजिक समुदाय नेताओं को शामिल किया जाना विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया ।

गरीबी रेखा ने नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का कार्यान्वयन करने हेतु **मुख्य कन्वर्जेंस तंत्र** अपनाए गए जो इस प्रकार हैं –

- खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग से बीपीएल परिवारों का डाटा संग्रहण करना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों का नामांकन करने के लिए श्रम विभाग को शामिल किया गया
- बीपीएल परिवारों को अवगत कराने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया गया
- बैंक कर्मचारियों ने खाता खुलवाने के लिए सभी बीपीएल परिवारों के घरों का दौरा किया
- बीपीएल परिवारों के खातों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी अंतरण हेतु प्रत्यक्ष लाभ से संबद्ध किया गया
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत विशेषकर निराश्रित महिलाओं और विधवाओं का नामांकन किया गया



## Group – Union Territories
## Best-performing – District-Chandigarh, Union Territory

### 1. Exemplary Work done in the District under the Scheme

More than two lakh twenty thousand Bank Accounts were opened under PMJDY. More than one lakh RuPay cards were activated out of about 1,82,000 issued. More than 1,60,000 account holders have deposited a total of Rs 59 crore in PMJDY accounts.

1,99,196 accounts seeded with Aadhaar under PMJDY. Aadhaar Enabled payment System (AEPS) is used for crediting scholarships to students. Adahaar enabled Bio Metric payment system is used to disburse Social Security Pensions. Aadhaar based Direct Benefit Transfer of LPG (DBTL) for LPG subsidy is also in vogue.

Close to 50 camps were organized for activation and distribution of RuPay Card. Mass targeted awareness generation was done through Radio FM, Print Media, Pamphlets, Councilors, Road shows.

State Bank of India (SBI) and Punjab National Bank (PNB) appointed Bank Mitras and 25 active Bank Mitras are successfully engaged in Chandigarh. 40,615 transactions worth Rs 30.28 crore were facilitated in the last three months by Bank Mitras. 16 Micro ATM are used by Bank Mitras for extending deposit and withdrawal facilities.

A door-to-door survey was done by the Aaganwadi workers to identify the left out beneficiaries. The Sampark Centres (Common Service Centers) were leveraged to gain access to beneficiaries.

Involvement of social community leaders like Village Sarpanch was especially ensured, for success of the initiative.

***Key convergence mechanisms*** for implementing PMJDY for Below Poverty Line (BPL) families included:

- Collecting BPL family Data from Food and Civil Supplies Department
- Involving Labour Department for enrolment under PMJDY for unorganized sector.
- Anganwadi workers were involved for sensitization of BPL families
- Visits by bank employees to all BPL family homes for account opening
- Linking all BPL family accounts to DBT for subsidy transfer under PDS
- Destitute women and widows specially enrolled under PMJDY

## 2. आम नागरिकों के लिए लाभ

अब बैंक खाता खोलना काफी आसान हो गया है क्योंकि खाता खोलने के लिए बैंक के कर्मचारी घर–घर जा रहे हैं । परिणामस्वरूप अब आम नागरिक बिना किसी निवासी प्रमाण–पत्र के अपना बैंक खाता खोलने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । केवल स्व–वचनबद्ध ही पर्याप्त हैं । वे अब शून्य शेष खाता खोलने की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रु. 30,000 / – का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। रु. 5,000 / – तक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी प्रदान की जा रही है जिससे चंडीगढ़ के आम नागरिकों को सामान्य मोबाइल फोन के जरिए बैलेंस देखने और धनराशि अंतरण करने की सुविधा मिली है ।

सरकारी स्कीमों के लाभार्थी अपने खातों में सीधा लाभ अंतरण प्राप्त कर रहे हैं । आधार संख्या प्राप्त नागरिकों को खाता खोलने के लिए जटिल प्रपत्रों को भरने की और कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वतः सृजित है । प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारक को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड का भी वितरण किया गया है जिसकी नागरिकों ने बहुत सराहना की है ।

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

***निर्धन व्यक्ति जो बैंक खाता खोलने का सपना भी नहीं देख सकते हैं, अब बैंक खाता धारक हैं और उससे जुड़ी सुविधाएं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं।*** इसी प्रकार, बीमा क्षेत्र जैसे जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जो गरीब या निम्न मध्य वर्ग के लिए अब तक अलभ्य था, अब प्रधानमंत्री जन धन योजना की बदौलत प्रत्येक परिवार के लिए एक आम सुविधा हो गई है । यह आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी के खाते खोले गए हैं अतः सीधे लाभ अंतरण स्कीम जरूरतमंद और गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं । प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ में कुल 2,22,853 खाते खोले गए और बैंकों में 60 करोड़ से अधिक रुपए जमा हुए।



## 2. Benefits to the Common Citizens

The opening of bank accounts has now become much easier since bank officials are canvassing door-to-door. As a result, common citizens now have the facility to open their bank accounts without any proof of residence. Only self-declaration is sufficient. They also now enjoy the facility to open zero balance account under PMJDY.

Life insurance cover of Rs 30,000/- is being provided under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Overdraft facilities up to Rs 5,000/- are also being given.

Mobile banking facilities are also being provided under the PMJDY which provide to the common citizens of Chandigarh, the facilities to check balance and transfer funds using ordinary cell phones.

Beneficiaries of Government Schemes are getting Direct Benefit Transfer into their accounts. Citizens carrying Aadhaar are not required to fill up complex forms anymore for opening an account since it is auto generated. Distribution of RuPay debit cards to the account holders is also free of cost under PMJDY, a benefit being welcomed by the citizens.

## 3. Impact of Scheme in the District

***Poor people, who did not even dream to have a bank account, are now operating one, availing the concomitant facilities and benefits.*** Similarly, life insurance and accidental insurance which were hitherto out of reach for the poor or lower middle class are now part of the bouquet of benefits in every household, thanks to PMJDY. It is a significant social security to the common man.

Since the accounts under PMJDY are opened for all citizens, DBT schemes are reaching the needy and poor. A total of 2,22,853 accounts are opened in Chandigarh and more than 60 crore deposited in them under the PMJDY.

## 2. आम नागरिकों के लिए लाभ

अब बैंक खाता खोलना काफी आसान हो गया है क्योंकि खाता खोलने के लिए बैंक के कर्मचारी घर–घर जा रहे हैं । परिणामस्वरूप अब आम नागरिक बिना किसी निवासी प्रमाण–पत्र के अपना बैंक खाता खोलने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । केवल स्व–वचनबद्ध ही पर्याप्त हैं । वे अब शून्य शेष खाता खोलने की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रु. 30,000/– का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। रु. 5,000/– तक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी प्रदान की जा रही है जिससे चंडीगढ़ के आम नागरिकों को सामान्य मोबाइल फोन के जरिए बैलेंस देखने और धनराशि अंतरण करने की सुविधा मिली है ।

सरकारी स्कीमों के लाभार्थी अपने खातों में सीधा लाभ अंतरण प्राप्त कर रहे हैं । आधार संख्या प्राप्त नागरिकों को खाता खोलने के लिए जटिल प्रपत्रों को भरने की और कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वतः सृजित है । प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारक को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड का भी वितरण किया गया है जिसकी नागरिकों ने बहुत सराहना की है ।

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

***निर्धन व्यक्ति जो बैंक खाता खोलने का सपना भी नहीं देख सकते हैं, अब बैंक खाता धारक हैं और उससे जुड़ी सुविधाएं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं।*** इसी प्रकार, बीमा क्षेत्र जैसे जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जो गरीब या निम्न मध्य वर्ग के लिए अब तक अलभ्य था, अब प्रधानमंत्री जन धन योजना की बदौलत प्रत्येक परिवार के लिए एक आम सुविधा हो गई है । यह आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है ।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी के खाते खोले गए हैं अतः सीधे लाभ अंतरण स्कीम जरूरतमंद और गरीब लोगों तक पहुंच रहे हैं । प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ में कुल 2,22,853 खाते खोले गए और बैंकों में 60 करोड़ से अधिक रुपए जमा हुए।



## 2. Benefits to the Common Citizens

The opening of bank accounts has now become much easier since bank officials are canvassing door-to-door. As a result, common citizens now have the facility to open their bank accounts without any proof of residence. Only self-declaration is sufficient. They also now enjoy the facility to open zero balance account under PMJDY.

Life insurance cover of Rs 30,000/- is being provided under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Overdraft facilities up to Rs 5,000/- are also being given.

Mobile banking facilities are also being provided under the PMJDY which provide to the common citizens of Chandigarh, the facilities to check balance and transfer funds using ordinary cell phones.

Beneficiaries of Government Schemes are getting Direct Benefit Transfer into their accounts. Citizens carrying Aadhaar are not required to fill up complex forms anymore for opening an account since it is auto generated. Distribution of RuPay debit cards to the account holders is also free of cost under PMJDY, a benefit being welcomed by the citizens.

## 3. Impact of Scheme in the District

***Poor people, who did not even dream to have a bank account, are now operating one, availing the concomitant facilities and benefits.*** Similarly, life insurance and accidental insurance which were hitherto out of reach for the poor or lower middle class are now part of the bouquet of benefits in every household, thanks to PMJDY. It is a significant social security to the common man.

Since the accounts under PMJDY are opened for all citizens, DBT schemes are reaching the needy and poor. A total of 2,22,853 accounts are opened in Chandigarh and more than 60 crore deposited in them under the PMJDY.

# स्वच्छ भारत (ग्रामीण)



# SWACHH BHARAT (GRAMIN)

# स्कीम का सार

स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण स्वच्छता के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया जिसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक खुले में शौच का उन्मूलन करना है । इसका लक्ष्य हमारे देश को स्वच्छ बनाने के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना है । इस स्कीम के अंतर्गत सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण भारत में 12 करोड़ शौचालय का निर्माण कर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है।



# Brief of the Scheme

Swachh Bharat Mission is a national campaign by the Government of India, for total sanitation. On 2 October, 2014, the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Mission, which aims at eradicating open defecation by 2019. Its goal is to fulfill the dream of the Father of our Nation, Mahatma Gandhi, of making our country clean. Under this scheme, the Government is aiming to achieve an Open Defecation Free (ODF) India by the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, by facilitating construction of 12 crore toilets in rural India, under Swachh Bharat Mission (Gramin).

## मानीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई

- समर्पित दौरे और रात्रि चौपाल, जिला कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें
- सतत प्रातः निगरानी (निगरानी समिति, स्कूली बच्चे, वानर सेना, मानव श्रृंखला, पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि)
- जांच करने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को सक्रिय करना : "एक अधिकारी, एक पंचायत"
- खुले में शौच जाने पर जुर्माना लगाना
- परवर्ती चरणों में अंतर जिला सत्यापन; राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर टीमों द्वारा सत्यापन; वर्ष 2015 में भारत सरकार के दो राष्ट्रीय स्तर मानीटरिंग (एनएलएम) समूहों द्वारा सत्यापन

## ग्राम पंचायतों के वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहन देना

- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम), निर्मल ग्राम पुरस्कार जैसे स्कीमों के अंतर्गत पुरस्कार
- सार्वजनिक समारोह (गरिमा सम्मेलन) में सफल ग्राम पंचायतों के सरपंचों को बधाई जिसमें सभी सरपंच भाग ले
- मीडिया का ध्यान आकर्षित करना
- सभी ग्राम पंचायतों की खुले शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति का मानचित्रण जिसे कलेक्टर कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए
- ट्रिगरिंग सत्र में समूह परामर्श के दौरान समुदाय को स्पष्टतया शौचालय का निर्माण करने के लिए नहीं कहा गया । इसके बजाय यह प्रयास किया गया कि समुदाय स्वयं यह महसूस करे और कहे कि शौचालयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है ।
- यह सुनिश्चित किया गया कि भुगतान कोई मुद्दा नहीं बने। मौद्रिक प्रोत्साहन को ध्यान में रखे बिना लोगों को शौचालयों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया । पात्र श्रेणियों में भुगतान को लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं देखकर पुरस्कार के रूप में देखा गया ।



## Monitoring and Follow up

- Dedicated Visits and Ratri Choupals, Regular Review meetings by the District Collector
- Continuous follow up during early mornings (by Nigrani Committees, school children, Vanar Senas, Human chain, Elected representatives of Panchayat)
- Setting in motion the whole administrative machinery to check: "One officer, One Panchayat"
- Penalizing those who defecate in the open
- Inter-district verification; Verification by State level and National level teams; Verification by 2 National Level Monitoring (NLM) groups of GoI in 2015.

## Incentivizing desirable behaviour by Gram Panchayats

- Rewards under schemes such as Solid & Liquid Waste Management (SLWM), Nirmal Gram Puraskar.
- Felicitation of Sarpanches of successful GPs at public function (Garima Sammellan) attended by all Sarpanches
- Media attention
- Open Defecation Free (ODF) status Mapping of all GPs prominently displayed at the Collectorate
- During group counseling in triggering sessions, the community was not explicitly advised to construct toilets. Instead, a successful attempt was made to let the community itself feel and state that they needed to build toilets.
- It was ensured that payment was never an issue. Attempts were made to encourage people to build toilets, irrespective of monetary incentive. The payment made to eligible categories, was thus seen as a reward, and not as reimbursement of costs.

## 2. आम नागरिकों के लिए लाभ

**महिलाओं की गरिमा और सुविधा**

- महिलाएं अक्सर शौचालय निर्माण करने के लिए अपने पति/ससुराल पक्ष पर दबाव डालती है
- असुविधा से बचाव (विशेषकर मासिक धर्म, गर्भावस्था आदि के दौरान)
- सुबह जल्दी जाने/सूरज छिपने तक देर रात तक इंतजार नहीं करना पड़ता ।
- घर में पर्दा और बाहर असम्मानजनक प्रदर्शन की विडम्बना ।

**महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा**

- अंधेरे में शौच के लिए जाने से सुरक्षा को खतरा होता है ।
- उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, यौन हमले का भय
- किसी अन्य द्वारा कृत्य का कैमरा फोन का उपयोग करने/फिल्म बनाने का भय

**खुले में शौच जाने हेतु खेत में जाने में लगने वाले समय की बचत**

**बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों का लक्ष्य प्राप्त करना**

- खुले में शौच से संबंधित बीमारियों और पोषण की कमी, अवरूद्ध विकास, उच्च शिशु मृत्यु दर (सीएमआर) के बीच उच्च सह संबंध
- दस्त, आंत के कीड़ों का संक्रमण, टाइफाइड, हैजा, हेपाटाइटिस, पोलियो आदि मामले कम हुए – पहले बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते थे ।
- स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, महिलाओं में मूत्र मार्ग में संक्रमण के मामले कम हुए जिसका उच्च मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के साथ उच्च सह संबंध था ।
- शौचालयों के निर्माण के साथ हाथ धोने के लिए साबुन का उपयोग करने, मासिक धर्म स्वच्छता आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

**विशेष श्रेणी**

- दिव्यांग व्यक्ति : जीवन आसान हुआ
- वृद्धावस्था में आराम



## 2. Benefits to the Common Citizens

**Dignity and comfort of women**

- Women often pressurized husbands/in-laws to build toilets
- Discomfort avoided (particularly during menstrual period, pregnancy etc.)
- No more compulsion to wait for early morning hours/late night when the sun was down
- The irony of veil inside home, and undignified exposure outside

**Safety issues of women**

- Going out in darkness implies more risk to safety
- Fear of harassment, molestation, sexual assault
- Fear of someone using camera phone/filming the act

**Time saved in traveling to the fields for open defecation**

**Achieving better Health indicators**

- High correlation between open defecation related diseases and under-nutrition, stunted growth, high Child Mortality Rate (CMR)
- Reduced incidence of Diarrhea, intestinal worm infection, typhoid, cholera, hepatitis, polio - Children were especially affected, earlier.
- Reduced incidence of gynecological problems and urinary tract infection in women, which had high correlation with high Maternal Mortality Rate (MMR)
- Along with construction of toilets, creation of awareness about using soap to wash hands, focus on menstrual hygiene, etc.

**Special Categories**

- *Divyang* Individuals: Life became easier
- Comfort in old age

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

**सामुदायिक संचालित अभियान**

- समुदायों में जागरूकता
- समुदायों में आत्मविश्वास का बढ़ना

**नेतृत्व**

- निगरानी का नेतृत्व करने के लिए स्वभाविक नेतृत्व का उदय
- आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका

**गांव में एकता**

- एक लक्ष्य : गांव का, गांव द्वारा, गांव के लिए
- पूर्व में कुछ क्षेत्रों में अलग–अलग जातियों के लिए अलग–अलग स्थान। अब गांव में एकता है।

**एक पंचायत, एक अधिकारी**

- आश्चर्यजनक प्रभाव – विद्यालय समय पर खुलना शुरू हुए क्योंकि शिक्षक भी प्रातः निगरानी में शामिल हुए ।

**डाटा कवरेज**

- ओडीएफ अभियान के अंतर्गत 290 ग्राम पंचायतों और इसके 1015 गांवों की 17 लाख ग्रामीण आबादी कवर हुई। 26 जनवरी, 2016 को बीकानेर को राजस्थान के पहले और भारत के दूसरे ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) जिले का दर्जा दिया गया।
- भारत सरकार के सत्यापन टीम द्वारा किए गए त्वरित आकलन अध्ययन में लगभग 97.8% आबादी द्वारा शौचालय का उपयोग करने के बारे में सूचित किया गया है । यह 2011 की जनगणना में सूचित 29%के कवरेज के मुकाबले अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है।



## 3. Impact of the Scheme in District

**Community led campaign**

- Awareness of the community
- Rising confidence of the community

**Leadership**

- Natural leaders emerged to lead follow up
- Active role of Anganwadi workers, ASHAs

**Unity of the village**

- One goal: Of the village, by the village, for the village
- Previously, separate pockets for separate castes at some places. Now, village stands united.

**One Panchayat, One Officer**

- Surprise side effect: Schools started to open in time, as teachers also joined in the follow up

**Data coverage**

- 17 lakh rural population covered under ODF campaign in the 290 Gram-panchayats and its 1015 villages. On 26 January, 2016, Bikaner was recognized as the first ODF district in Rajasthan, and the second in India.
- In a rapid assessment study by the Government of India verification team, around 97.8% population reported using toilets. This is a huge increase from the 29% coverage reported in 2011 Census.

# समूह – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य
# श्रेष्ठ जिला – पश्चिम सिक्किम, सिक्किम

## 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किया गया । तद्नुसार जिले में आधार सर्वेक्षण 2012 के लक्ष्यों की पुनः समीक्षा की गई । नए लक्ष्य निर्धारित किए गए जिससे 3118 घरेलू शौचालय का निर्माण करना आवश्यक हो गया और स्वच्छ घरेलू शौचालय का निर्माण मिशन मोड में आरंभ किया गया ।

लाभार्थी–प्रेरित कार्यान्वयन पद्धति अपनाई गई एवं घरेलू शौचालयों के लिए स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। शौचालय निर्माण में सामुदायिक भागीदारी करके स्कूलों में शौचालय, हाथ धोने के स्थान निर्माण आदि करने के लिए मृत संबंधियों के नाम पर अंशदान करना एक नवीन पहल है।

शेष बचे घरेलू शौचालय और कूड़ा उठाने वाले वाहन के लिए पंचायत निधि से अंशदान दिया गया । इस प्रकार सभी स्तरों पर पंचायतों की सुनिश्चित भागीदारी हुई । स्कीम के अंतर्गत प्रगति को मानीटर करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एकक (जीपीयू) में समर्पित **"स्वच्छता प्रेरक"** की नियुक्ति की गई ।

अन्य स्कीमों के साथ कुशलतापूर्वक कन्वर्जेंस का लक्ष्य प्राप्त किया गया। आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) कार्यकलाप आयोजित किए गए जिनमें रैलियां, स्वच्छता अभियान, स्कूल समारोह, बैठकें शामिल हैं । परिणामस्वरूप 3258 घरेलू शौचालय और 42 सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्स का निर्माण किया जा सका । 31 दिसम्बर, 2015 को विशेष ग्राम सभा द्वारा जिले के सभी 55 ग्राम पंचायत एकक को खुले शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया ।

## 2. आम नागरिकों को लाभ

अब प्रत्येक परिवार में घरेलू शौचालय है । जिले में स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ जिससे नागरिकों को बीमारी संबंधी व्यय में कमी का आनुषंगिक लाभ हुआ और चिकित्सा व्यय के लिए खर्च में कमी आई ।

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

इस क्षेत्र में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन के तौर पर लाभप्रद प्रभाव – नैपकिन उत्पादन यूनिट शुरू हुए। विद्यालयों और घरों में शून्य कचरा प्रबंधन अभियान शुरू हुए। कचरे का समुचित रूप से निपटान करने के लिए सभी टैक्सियों को कूड़ा बैग दिए गए।

राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश और निकास द्वार पर प्लास्टिक तथा अन्य डिस्पोजेबल कचरे पर नजर रखने से राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र में कचरा प्रबंधन में सहायता मिली। अब स्वच्छता जीवन पद्धति है और यह केवल शौचालयों तक सीमित नहीं है।



# Group – North East & Hill States
# Best performing – District-West Sikkim, Sikkim

## 1. Exemplary Work done in District under the Scheme

SBM (G) was launched on 2 October, 2014. Accordingly, baseline survey 2012 targets were reviewed afresh in the district. New targets were arrived at, necessitating construction of 3118 Individual Household Latrines (IHHLs) and building of sanitary IHHLs started in mission mode manner.

Beneficiary-driven implementation approach was adopted, encouraging use of local materials for IHHLs. Community participation in making toilets through contribution of funds in the names of deceased relatives for making toilets, washstands at schools etc. is an innovative approach.

Panchayat funds contributed for left out IHHLs and garbage vehicles. Thus, involvement of panchayats at all levels ensured support. Dedicated "Swachhta Prerak" appointed in each Gram Panchayat Unit (GPU) to monitor the progress under the Scheme. Convergence with other schemes was achieved effectively. IEC (Information, Education and Communication) activities comprising rallies, cleanliness drives, school events, meetings were organized. As a result, 3258 IHHLs and 42 Community Sanitary Complexes could be constructed. On 31 Dec, 2015, all 55 GPUs of district were declared ODF through Special Gram Sabha.

## 2. Benefits to the Common Citizens

Every household now has an IHHL. Health indicators in the district are improving significantly, with attendant benefits of reduced disease burden for the citizen, as well as reduced cash outflow for medical expenses.

## 3. Impact of the Scheme in District

Beneficial effect in the area in the form of menstrual hygiene management – opening of sanitary napkin production unit. Zero waste management campaigns started in schools and households. Garbage bags given to all taxis to properly manage waste.

Keeping track of plastic and other disposable waste at entry and exit point of National park has helped in waste management in the ecosystem of National Park. Swachhta is now a way of life in the district, not limited to toilets alone.

# स्वच्छ विद्यालय

# SWACHH VIDYALAYA

# स्कीम का सार

**स्वच्छ विद्यालय** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की 15 अगस्त, 2015 तक प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यशील शौचालय सुनिश्चित करने की एक पहल है । 25 मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों ने इस अभियान के लिए 400 करोड़ रु. प्रतिभूत किए हैं तथा निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को विद्यालयों में शौचालय ब्लॉकों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है । इस अभियान की एक मुख्य विशेषता यह सुनिश्चित करना था कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में जल, सफाई और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) सुविधाओं का कार्यशील और सुव्यवस्थित सेट हो । विद्यालयों में जल, सफाई और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) तकनीकी और मानव विकास घटकों का सशक्त मिश्रण है जो उत्तम विद्यालय परिवेश का निर्माण करने के लिए आवश्यक है ताकि बच्चों के बीच उचित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व्यवहारों के विकास में सहायता की जा सके । तकनीकी घटक में विद्यालय परिसर में बच्चों और शिक्षकों के उपयोग हेतु पेयजल, हाथ धोने, शौचालय और साबुन की सुविधाएं शामिल हैं । मानव विकास घटक वे कार्यकलाप हैं जिनमें विद्यालय के भीतर की स्थिति और बच्चों को ऐसे व्यवहार को अपनाने में सहायता करना है जो जल जनित, सफाई और स्वच्छता संबंधी बीमारियों की रोकथाम में सहायक हो सके ।



# Brief of the Scheme

**Swachh Vidyalaya** is an initiative of Ministry of Human Resource Development, Government of India to ensure a functional toilet in every school by 15 August, 2015. Public sector units under 25 Ministries pledged Rs. 400 crore for the campaign and private and public sector companies encouraged to build toilet blocks in schools. A key feature of the campaign was to ensure that every school in India has a set of functioning and well maintained water, sanitation and hygiene (WASH) facilities. WASH in schools is a potent combination of technical and human development components necessary to produce a healthy school environment so as to develop and support appropriate health and hygiene behaviour among the children. The technical components include drinking water, hand-wash, toilet and soap facilities in the school compound for use by children and teachers. The human development components are the activities that promote conditions within the school and the practices of children that help to observe clean habits and prevent water, hygiene and sanitation related diseases.

# समूह – अन्य राज्य
# श्रेष्ठ जिला – अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश

## 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कियों के लिए 2200 से अधिक आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया गया जहां पानी की निरंतर व्यवस्था थी । 660 से अधिक पुराने शौचालयों को तोड़कर नए शौचालयों का निर्माण किया गया । 1000 से अधिक खराब शौचालयों की मरम्मत की गई और उनको उपयोग करने योग्य बनाया गया ।

शौचालयों का निर्माण कार्य 3 महीने के रिकार्ड समय के अंदर पूरा किया गया। स्वच्छ विद्यालय स्कीम के अंतर्गत 2774 प्राथमिक विद्यालय, 595 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 608 जिला परिषद एवं नगरपालिका उच्च विद्यालयों को कवर किया गया।

दिन में दो बार विद्यालय के शौचालयों की सफाई करने के लिए प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में क्रमशः रु. 2000/–, रु. 2500/–, रु. 4000/– के पारिश्रमिक पर स्वच्छता स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई ।

## 2. आम नागरिकों को लाभ

विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण से विद्यालय के आस–पास के क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता आई है तथा खुले स्थान में शौच जाने का व्यवहार बंद हो गया । सरकारी विद्यालयों के आस–पास रहने वाले लोग भी खुश हैं क्योंकि विद्यार्थी शौच के लिए खुले स्थानों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ।

स्वच्छ विद्यालय की सफलता से अभिप्रेरित होकर, अब विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों में शौचालय निर्माण के लिए अपने अभिभावकों को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं ।

जिला प्रशासन ने खुले शौच से मुक्त (ओडीएफ) 111 गांवों की पहचान की है तथा गांवों में निजी घरेलू शौचालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु प्रत्येक 2 अथवा 3 ओडीएफ गांवों के लिए विशेष अधिकारी के रूप में जिला स्तरीय अधिकारी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत 111 चिन्हित ओडीएफ गांवों में विद्यालय शौचालय तथा निजी घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया ।

स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत शौचालय के निर्माण से नागरिकों में सफाई एवं स्वच्छता के संबंध में प्रखर जागरूकता उत्पन्न हुई ।



# Group – Other States
# Best performing – District-Ananthapuramu, Andhra Pradesh

## 1. Exemplary Work Done Under the Scheme

Under Swachh Vidyalaya, more than 2200 Modern toilets were constructed for boys and girls with running water facility. More than 660 dilapidated toilets were demolished and newly reconstructed. More than 1000 non-functional toilets were repaired and made functional.

Construction of toilets was completed within a record time of 3 months. 2774 Primary Schools, 595 Upper Primary Schools and 608 Zilla Parishad and Municipal High Schools were covered under the Swachh Vidyalaya Scheme.

Sanitation volunteers were appointed for cleaning school toilets, twice a day, with a remuneration of Rs.2000/- , Rs.2500/- and Rs.4000/- in Primary Schools, Upper Primary Schools and High Schools respectively.

## 2. Benefit to the Common Citizens

Construction of toilets in the Schools brought social awareness in the surrounding areas of the schools and the practices of open defecation stopped. People residing near government schools are feeling happy, since the students are not using open places for urinals and defecation.

Motivated by the Swatch Vidyalaya success, students are now educating and prevailing upon their parents to construct toilets in their houses to promote the Swachh Bharat Mission.

The district administration has identified 111 villages as ODF and a District level Officer has been appointed as a special officer for every 2-3 ODF villages for speedy completion of individual household toilets in the villages. Simultaneously, school toilets were constructed under Swachh Vidyalaya in 111 identified ODF villages along with individual household toilets.

Construction of toilets under Swachh Vidyalaya in the schools brought high awareness on sanitation and hygiene among the citizens.

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण से पूर्व विद्यालय में छात्राओं को शौच हेतु कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था । शौच के लिए खुले में जाने से उन्हें शर्मिंदगी और असुरक्षा महसूस होती थी । अब ऐसी स्थिति नहीं है ।

छात्राओं के विद्यालय छोड़ने की दर 15% से कम होकर 10% तक हो गई है तथा नामांकन में सराहनीय रूप से वृद्धि हुई है । लड़कियों के लिए अलग शौचालय की उपलब्धता के कारण अभिभावक बिना किसी हिचक के अपनी लड़कियों को मासिक चक्र के दौरान भी विद्यालय भेज रहे हैं ।

विद्यार्थी बिना किसी संकोच के तनावमुक्त परिवेश में आनंदपूर्वक कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं । अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति और स्वयं सहायता समूह अपना उत्तरदायित्व समझ रहे हैं और स्वयं स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं एवं स्वच्छ विद्यालय शौचालयों के रख–रखाव की मॉनीटरिंग कर रहे हैं ।



## 3. Impact of the Scheme in the District

Before the construction of toilets under Swachh Vidyalaya, girl students faced severe problems to attend to nature calls. They felt shy and insecure to go to open places for urinals. Such is not the situation now.

Drop-out rate of girl students has reduced from 15% to 10% and enrollment has increased appreciably. Because of the availability of separate toilets for girls, parents have no hesitation in sending their children to the school even during the menstrual period also.

Students are happily attending the classes without any hesitation and in a stress-free environment. Parents, School Management Committees and the Self Help Group members are feeling responsible, willingly involving themselves and monitoring the maintenance of Swachh Vidyalaya toilets.

## समूह – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य
## श्रेष्ठ जिला – अनंतनाग, जम्मू व कश्मीर

### 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

अनंतनाग जिले के सभी विद्यालयों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत शौचालय सुविधा से कवर किया गया है । इसमें लड़कियों के लिए अलग शौचालय शामिल हैं । यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के निरीक्षण में शुरू किया गया । गांव शिक्षा समितियों (वीईसी) को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया गया । इससे समुदाय के सदस्यों के मध्य अपनेपन की भावना विकसित हुई जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य निर्धारित समय के अंदर प्राप्त किया गया ।

जिला प्रशासन ने उप मंडल मजिस्ट्रेटों और तहसीलदारों की मानीटरिंग/सहायक टीमें गठित की ताकि निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित हो सके ।

तकनीकी स्कंध को यह कड़े निर्देश दिए गए कि इन शौचालयों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। निर्माण प्रक्रिया की प्रभावी मानीटरिंग करने के लिए त्रिस्तरीय मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया । इसमें पहले स्तर पर जिला प्रशासन, दूसरे स्तर पर शिक्षा विभाग और तीसरे स्तर पर आंचलिक स्तर के विभागीय अधिकारी शामिल थे ।

इस प्रकार के व्यापक निर्माणों में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर दोबारा जांच की गई ।

सभी विद्यालयों जिनमें इस प्रकार के निर्माण कार्य किए गए, के प्रधानाध्यापकों को यह सलाह दी गई कि निर्माण प्रक्रिया में किसी प्रकार के विचलन से बचने के लिए कार्य रजिस्टर रखा जाए । संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को इस प्रकार के निर्माणों का समुचित रिकार्ड रखने की सलाह दी गई जिसे लेखा परीक्षा द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके ।

इन शौचालयों के किए गए सभी कार्यों के दावों की पहले सामाजिक संपरीक्षा की गई । प्रत्येक प्रकार के पूर्वोपाय किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित समय–सीमा से पूर्व निर्माण कार्य संपन्न हो । इसे संस्थान प्रमुखों/आचंलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर नियमित समीक्षा करके सुनिश्चित किया गया ।

सभी संस्थानों के प्रमुख ने इन शौचालयों के रख–रखाव और स्वच्छता को सुनिश्चित किया । उन्हें यह सलाह दी गई थी कि इस वित्तीय विवक्षा को स्कूल के स्थानीय निधियों से पूरा किया जाए।



## Group – North East and Hill States
## Best performing – District-Anantnag, Jammu & Kashmir

### 1. Exemplary Work done under the Scheme

All the schools in district Anantnag have been covered with toilet facility under different schemes. This included separate toilets for girls. The programme was taken-up under the supervision of the District Administration. The Village Education Committees (VEC) were actively involved. This inculcated a sense of belongingness among the community members, as a result of which the target was achieved within the stipulated time.

The District Administration constituted the monitoring/facilitating teams comprising Sub Divisional Magistrates and Tehsildars to ensure hassle-free and quality construction.

The technical wing was given strict instructions to ensure the good quality of construction of these toilets. Three tier monitoring mechanism was put in place for effective monitoring of the construction process. This included 1st level by the District Administration, 2nd by the Education Department and 3rd at the Zonal level comprising officers of the Department.

In order to maintain transparency in such large-scale construction activities, cross verification at different levels was undertaken.

All the Heads of the schools where such constructions were carried out were advised to maintain the works register in order to avoid any deviation in the construction process. The Heads of the institutions concerned have been advised to maintain proper records for such constructions which could be produced before the audit at any point of time.

All the Work Done claims of these toilets have undergone through Social Audit. Every precautionary measure was taken to ensure the completion of construction before given time line. This was ensured by way of regular reviews on daily basis by the Heads of the Institutions / Zonal Education Officer.

All the Heads of the Institutions are ensuring good maintenance, upkeep and cleanliness of these toilets. They have been advised to meet the financial implications out of the school local funds.

## 2. आम नागरिकों को लाभ

विद्यार्थियों के बीच जागरूकता और ग्राह्यता को विद्यालय में एक नियमित चर्या बनाया गया ताकि शौचालयों के रख–रखाव और स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके । सहपाठी विद्यार्थियों को अवगत कराने, मानीटर और प्रेरित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी समितियां गठित की गई ।

प्रातःकाल की प्रार्थना सभा के दौरान विशेष स्वच्छता अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें विद्यार्थियों को हमेशा शौचालय का उपयोग करने और कभी भी खुले में शौच नहीं जाने के बारे में शिक्षित किया गया क्योंकि इनसे बीमारियां फैलती हैं ।

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

समुदाय के सदस्यों ने यह महसूस करना शुरू किया कि विद्यालय समुदाय से संबंधित है और उनके बच्चों को विद्यालय में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है ।

समुदाय के सदस्यों ने भूखंड की पहचान करने/दान करने में विद्यालयों की सहायता की जहां विद्यालय परिसर के अंदर निर्माण करने हेतु भूमि व्यावहारिक नहीं थी । कुछ स्थानों पर समुदाय के सदस्यों ने इन शौचालयों के रख–रखाव की जिम्मेदारी लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त की ।

विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता संबंधी आदतों को आत्मसात करने के पश्चात उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया गया । दूर–दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी जिनके परिवार सामान्यतः अपने घरों में इस प्रकार की सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की सुविधा विद्यालय में उपस्थिति का एक प्रेरक घटक बन गया ।

इस पहल से विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं की उपस्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा । ऐसी छात्राएं जो शौचालय के उपलब्धता के अभाव में विद्यालय से अनुपस्थित रहती थी, ने नियमित रूप से विद्यालय आना शुरू कर दिया ।

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी), वीईसी, स्थानीय वक्फ बोर्ड, पंचायती राज संस्थानों, एसएमडीसी और गैर–सरकारी संगठन को जमीनी स्तर पर सम्मिलित करके किया गया । ग्रामीण विकास विभाग को किराए के भवनों के लिए इस सुविधा की व्यवस्था करने के लिए शामिल किया गया अन्यथा वे सुविधा रहित रह जाते ।



## 2. Benefits to the Common Citizens

Awareness-cum-sensitization among the students has been made a regular feature in schools to ensure the maintenance and cleanliness of toilets. Student Committees were constituted in every school to sensitize, monitor and motivate the fellow students.

Special cleanliness-oriented programmes are being conducted during morning assembly where students are being educated to always use the toilets and never defecate in the open as it leads to spread of diseases.

## 3. Impact of the Scheme in the District

The community members started feeling that the school belongs to the entire community and that it needs to get actively involved in ensuring provision of facilities to their wards.

The community members supported the schools in identifying and donating patches of land where it was not feasible for construction in the premises itself. At some of the places, the community members came forward with a commitment to take the responsibility of maintenance of these toilets.

Positive behavioral changes among the students were felt, after they imbibed the habits of cleanliness. The students in far-flung areas come from families which usually do not have such facility at their homes, so the provision of such facility became a motivating factor for such students to attend the school.

The initiative had a good impact on the attendance especially of girl students. Those girls who had to remain absent due to non-availability of toilets started attending school regularly.

The implementation was carried out on the ground level by involving School Management Committees (SMCs), VECs, local Wakf Boards, Panchayati Raj Institutions and NGOs. The Rural Development Department was also roped in to put this facility in place for rented buildings which would otherwise had remained uncovered.

## समूह – संघ राज्य क्षेत्र
## श्रेष्ठ जिला – दादरा एवं नागर हवेली

### 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

वर्ष 2015 में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग 50 से अधिक शौचालय ब्लॉक बनाए गए जिनमें उचित संकेत अंकित किए गए थे । जिला पंचायत, दादरा एवं नागर हवेली के पीडब्ल्यूडी विंग द्वारा शौचालयों के निर्माण एवं रख–रखाव की नियमित मॉनीटरिंग की गई । उन्होंने नियमित मानीटरिंग करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे कि वाट्सअप, स्मार्ट फोन आदि का उपयोग किया ।

शौचालय के निर्माण एवं रख–रखाव कार्य के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। विकलांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण करने हेतु विशेष ध्यान दिया गया ।

सभी विद्यालयों में शौचालयों की सफाई हेतु आवश्यक सभी बुनियादी सामग्री (पौछा, वाइपर, झाड़ू, फिनाइल, बाल्टी आदि) उपलब्ध कराए गए । टंकियों की नियमित सफाई की गई । पीने के पानी के लिए अलग नल लगाए गए ।

सभी विद्यालयों में रिवर्स ओस्मोसिस (आर ओ) की सुविधा प्रदान की गई । दादरा एवं नागर हवेली में सभी विद्यार्थियों (लगभग 50000) को स्वच्छता सेनानी के रूप में नियुक्त किया गया है जो परिवर्तन एजेंट के तौर पर समाज में स्वच्छता का संदेश फैला रहे हैं ।

अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु स्थानीय निकायों – जिला पंचायत शिक्षा समिति और सिलवासा नगर परिषद मुख्य स्टेकहोल्डर बनाए गए ।

दिनांक 2 अक्तूबर, 2015 को विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित रैली आयोजित की गई । इस मिशन को विद्यालयों के समग्र समय–सारणी के एक भाग के रूप में शामिल किया गया । प्रत्येक माह स्वच्छता अभियान के लिए विशेष दिन निर्धारित किए गए ।

### 2. आम नागरिकों को लाभ

बेहतर, साफ और स्वच्छ विद्यालय परिवेश तथा विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों एवं विकलांग बच्चों के लिए शौचालय की उपलब्धता और सुलभता के कारण अभिभावकों के बीच विश्वास जागृत हुआ है ।

सफाई और स्वच्छता से संबंधित आदतें बच्चों के माध्यम से उनके परिवारों तक प्रसारित हुई । "आत्मविश्वासी बनें" स्कीम के परिणामस्वरूप सैनीटरी नैपकीन के उपयोग में वृद्धि हुई है तथा आदिवासी परिवारों की जिन छात्राओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया, उन परिवारों के अन्य महिला सदस्यों को मासिक धर्म स्वच्छता की बेहतर जानकारी प्राप्त हुई ।

सीनीय निकाय संस्थानों अर्थात् पंचायत और नगर परिषद को सुदृढ़ बनाया गया क्योंकि स्वच्छ विद्यालय मिशन के घटक में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही।



## Group – Union Territories
## Best performing – District-Dadra & Nagar Haveli

### 1. Exemplary Work done under the Scheme

More than fifty toilet blocks comprising separate toilets for boys and girls were constructed in 2015, with appropriate signage. Construction and maintenance of toilets was monitored by the PWD wing of District Panchayat, Dadra & Nagar Haveli. They used modern technologies such as Whatsapp, Smart Phones, etc. for regular monitoring.

Online tendering process followed for award of work for construction and maintenance of toilets. Focused attention was given to making the toilets for Children with Special Needs (CWSN).

All the basic equipments (mops, wipers, brooms, phenyl, buckets etc.) required for cleaning toilets were provided in all the schools. Overhead tanks were regularly cleaned. Separate taps were installed for drinking water.

Reverse Osmosis (RO) facility was provided in all the schools. All the students (approx 500,00) were appointed as Swachhata Senani in Dadra & Nagar Haveli to work as change agents in the society in spreading the message of cleanliness.

Local bodies were made key stakeholders for successful implementation of the campaign – Education Committees of District Panchayat and Silvassa Municipal Council.

Rallies organized on 2 October, 2015 by the students on Swachh Bharat Mission. The Mission was included as a part of overall schedule of the schools. Special days were allocated every month for cleanliness drives and campaigns.

### 2. Benefits to the Common Citizens

A sense of confidence amongst parents is generated due to better, clean and hygienic school environment and availability and accessibility of toilets for students, specially for girls and CWSN.

Habits related to cleanliness and hygiene spread to the families of the children. "Being Confident" Scheme has resulted in increased use of Sanitary Napkins and better knowledge of menstrual hygiene amongst the female members of the tribal families of the girl students who were imparted necessary training.

Institutions of Local Bodies viz. Panchayat and Municipal Council got strengthened as elected representatives were actively involved in the components of Swachh Vidyalaya Mission.

## 3. जिलें में स्कीम का प्रभाव

शौचालयों की उपलब्धता और सुलभता के कारण निजता और सुरक्षा सुनिश्चित होने से कक्षा–I से कक्षा–XII तक लड़कियों के दाखिले की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015–16 में बढ़कर 683 हो गई ।

मासिक धर्म स्वच्छता की उचित जानकारी और साफ–सफाई सुविधाओं की सुलभता के कारण लड़कियों की उपस्थिति 90% से अधिक रिकार्ड की गई । विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के सामान्य स्वास्थ्य और समग्र स्वच्छता में सुधार के परिणामस्वरूप इनकी उपस्थिति में वृद्धि हुई है ।

स्वच्छता एवं विद्यालयों में दिए जाने वाले स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन के मध्य निकट संबद्धता के कारण बच्चे उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर प्रदर्शन से लाभान्वित हुए हैं । विद्यालय में स्वच्छता की संस्कृति विकसित होने के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का शिक्षण बेहतर हुआ है और विद्यालय के कार्यकलापों में उनकी सहभागिता बढ़ी है तथा विद्यालय में शिक्षा में बेहतर नतीजे प्राप्त हो रहे हैं।

स्वच्छ विद्यालय मिशन ने विद्यालयों में सफाई, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संबंध में विवेक जागृत किया है और नए उत्साह का संचार किया है।



## 3. Impact of the Scheme in District

Admission of girls from Class I to Class XII increased by 683 in 2015-16 compared to previous year because of availability and easy accessibility of toilets ensuring privacy and safety.

Attendance of girls above 90% was recorded because of proper knowledge of menstrual hygiene and easy accessibility of wash facilities. General health and overall hygiene of students and teachers improved, resulting in higher attendance.

Due to close linkages between hygiene and school nutrition, children benefitted with good health and better productivity. A culture of Swachhata was inculcated in schools resulting in better learning by students, their increased participation in school activities and gaining better outcomes from school education.

Swachh Vidyalaya Mission has aroused conscience and generated new enthusiasm about cleanliness, health, sanitation and hygiene in schools.

# मृदा स्वास्थ्य कार्ड



# SOIL HEALTH CARD

# स्कीम का सार

मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में शुरू की गई । इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं । इन कार्डों में किसानों की सहायता करने के लिए अलग–अलग खेतों हेतु फसल–वार पोषक तत्वों और खादों की संस्तुति होती है ताकि कृषि में लगने वाले बीज, खाद आदि के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उत्पादकता को बेहतर किया जा सके ।

मिट्टी के सभी नमूनों की पूरे देश के विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांच की जा रही है । तत्पश्चात विशेषज्ञ द्वारा मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सहित मृदा की सशक्तता और कमी का विश्लेषण किया जाता है तथा उर्वरकों के विवेकसम्मत उपयोग का सुझाव दिया जाता है। इन निष्कर्षों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भी प्रदर्शित किया जाता है। यह संभावना है कि 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा ।



# Brief of the Scheme

The Soil Health Card Scheme was launched by the Government of India in February 2015. Under the Scheme, the Soil Health Cards are issued to farmers. The Cards have crop-wise recommendations of nutrients and fertilizers required for the individual farms to help farmers to improve productivity through judicious use of inputs.

Soil samples are being tested in various labs across the country. Thereafter experts are analyzing the strengths and weaknesses including of micro-nutrient deficiencies of the soil and are suggesting measures for judicious fertilizer usage. The results too are displayed on the Cards. It is expected that 14 crore farmers would be issued SHCs.

## समूह – अन्य राज्य
## श्रेष्ठ जिला – बलरामपुर, छत्तीसगढ़

### 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

लगभग 60.16 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के साथ यहां के अधिकांश नागरिकों के लिए जीविका का प्राथमिक साधन कृषि होने के कारण जिला प्रशासन ने उत्पादकता में सुधार करने तथा किसानों के कल्याण के लिए खेती की लागत को कम करने के लिए प्रमुख पहल कार्य किए हैं । पहला कदम मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के अंतर्गत मिट्टी का नमूना संग्रह करना और वैज्ञानिक रूप से सृजित रिपोर्टों के आधार पर इनपुट का सुझाव देना है ।

मृदा परीक्षण परियोजना कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के सम्मिलित प्रयासों से चलाई जा रही है। कृषि और उद्यान विभाग जागरूकता उत्पन्न करने और मिट्टी का नमूना संग्रहण करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी सहायता और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आरएईओ) तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों (एसएडीओ) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उचित मृदा परीक्षण सुविधाएं नहीं होने की समस्या का निराकरण मिट्टी के नमूने को अम्बिकापुर, बिलासपुर और इलाहाबाद स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेज कर किया गया । 24 मृदा परीक्षण किट के साथ 13 मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) स्कीम से 30 लाख रु. की राशि के वित्तीय संसाधन का भी उपयोग किया गया । इससे अब यह सुनिश्चित हुआ है कि मृदा परीक्षण जिले में ही किया जा सकता है जिससे इस कार्यक्रम के और अधिक विस्तार में सुधार हुआ ।

मृदा परीक्षण किट का परिचालन करने के लिए ब्लॉक *प्रौद्योगिकी प्रबंधकों (बीटीएम)* और सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधकों (एटीएम) को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी स्कीम (एटीएमए) के अंतर्गत प्रशिक्षण करने हेतु नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, हैदराबाद से विशेषज्ञों को बुलाया गया ।

आरएईओ तथा एसएडीओ ने किसानों को केवीके के मृदा वैज्ञानिकों और ब्लॉक स्तर अधिकारियों के तकनीकी निरीक्षण के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उगाए जाने वाले फसलों और प्रयुक्त किए जाने वाले इनपुट के संबंध में मार्गदर्शन किया । मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) स्कीम के तहत विभिन्न जल और मृदा संरक्षण ढांचों का निर्माण करके मृदा अपक्षरण और वन–कटाई के मुद्दों का समाधान करने का भी प्रयास किया गया ।

जैविक कार्बन की मात्रा को बेहतर करने तथा मिट्टी से नाइट्रोजन के बह जाने को कम करने के लिए जैविक खेती, गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) और सघन धान प्रणाली (श्री) भी शुरू की गई है।



## Group – Other States
## Best performing – District-Balrampur, Chhattisgarh

### 1. Exemplary Work done in the District under the Scheme

With agricultural land spread over about 60.16 lakh hectares, being the primary occupation of a large majority of the citizens here, the district administration has taken major initiatives to improve productivity and reduce input costs for the betterment of farmers. The first step is to collect soil samples under the Soil Health Card Scheme and suggest inputs based on scientifically-generated reports.

The Soil Testing project is being run with the concerted efforts of the Department of Agriculture, Department of Horticulture and Krishi Vigyan Kendra (KVK) in the District. While the Agriculture and Horticulture departments have provided adequate human resource for awareness-generation and soil-sample collection, the Krishi Vigyan Kendra has provided technical help and training to the Rural Agriculture Extension Officers (RAEOs) and Senior Agriculture Development Officers (SADOs).

The issue of not having proper soil testing facilities locally was addressed by sending the samples to the labs in Ambikapur, Bilaspur and Allahabad. financial resources to the tune of Rs. 30 lakh from the Additional Central Assistance (ACA) Scheme were also utilized to set up 13 soil testing labs with 24 soil testing kits. This has now ensured that soil testing can be carried out in the District itself which has further improved the scale and outreach of the programme.

Specialists from Nagarjuna Fertilizers, Hyderabad were brought in to train the Block Technology Managers (BTMs) and Assistant Technology Managers (ATMs) under the Agricultural Technology Management Agency (ATMA) Scheme, for operating the soil testing kits.

The RAEOs and SADOs have provided guidance to farmers on crops to be grown and inputs to be used based on the Soil Health Card under technical supervision of the Soil Scientist at KVK and the Block Level Officials. Efforts have also been made to address issues of soil erosion and deforestation by constructing various water and soil conservation structures under MGNREGA Scheme.

Organic farming, Non-Pesticide Management (NPM) and System of Rice Intensification (SRI) have also been introduced for improving the organic carbon content and reduce nitrogen leaching in the soil.

## 2. किसानों के लिए लाभ

प्रारंभिक किसान आधार सर्वेक्षण से पता चला कि मिट्टी की आवश्यकता और प्रदत्त इनपुट के बीच अत्यल्प समानता तथा स्कीम के बारे में जागरुकता का अभाव प्रमुख चुनौती है। राज्य द्वारा निर्धारित खाद वितरण लक्ष्य और जिले तथा किसानों की मृदा स्वास्थ्य आवश्यकता के बीच भी असमानता है।

इस प्रकार किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड के निष्कर्षों के आधार पर इनपुट्स और सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया गया है। 14000 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया है तथा अब वे वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर इनपुट्स का उपयोग कर रहे हैं।

जिले में 24 लघु प्रयोगशाला सहित 13 केंद्र है जो प्रतिदिन 400 नमूनों की जांच कर सकते हैं। किसानों को अनेक स्कीमों जैसे कि मनरेगा (एमजीएनआईजीए), कृषि विभाग और उद्यान विभाग से इनपुट प्रदान कराने के भी प्रयास किए गए हैं ताकि किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

किसानों को जैविक खेती करने, गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) और श्री (सघन धान प्रणाली) आधारित खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता में सुधार किया जा सके और किसानों की लगने वाली लागत को कम किया जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त किसान मृदा जांच के लाभों से अवगत हैं तथा अपनी खेती प्रणालियों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिले सुझावों को सम्मिलित कर रहे हैं।

विशेष पहल जैसे कि जैविक खेती और श्री में किसानों के प्रशिक्षण से किसानों को कृषि में वैज्ञानिक पद्धतियों की आवश्यकता को समझने में सहायता मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) स्वयं सहायता समूह ने समुदाय को संगठित करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड परामर्श आधारित खेती के लाभों के बारे में महिला किसानों को अवगत कराने में भूमिका निभाई है।



## 2. Benefits to the Farmers

Initial farmer baseline surveys revealed poor match between soil requirements and inputs provided and lack of awareness about the Scheme, as major challenges. There was also a mismatch between fertilizer distribution targets set by state and soil health needs of district and farmers.

Thus, emphasis was laid on providing inputs and services based on Soil Health Card findings for the farmers. 14000 farmers have been provided with Soil Health Cards and are now using inputs based on scientific reports.

13 centers with 24 minilabs are now operational in the district which can test up to 400 samples every day. Efforts have also been made to provide the farmers with inputs from multiple schemes like MGNREGA, Agriculture department and Horticulture department so as to provide maximum benefits to the farmers.

Farmers are being motivated to take up organic farming, NPM and SRI based farming to improve productivity and reduce costs of input for the farmers. The farmers provided with Soil Health Cards are aware of the benefits of soil testing and are incorporating suggestions obtained from the Soil Health Cards in their farming methods.

Special initiatives like training of farmers in organic farming and SRI have further helped the farmers understand the need for scientific methods in agriculture. National Rural Livelihoods Mission (NRLM) Self-Help Groups (SHGs) have played a role in mobilizing the community and making the women farmers aware of the benefits of SHC-advisory based farming.

## 2. जिले में स्कीम का प्रभाव

जिले में मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण से पहचाने गए मुद्दों का समाधान करने के लिए जिले ने प्रमुख पहल किए हैं । जिले की औसत मृदा स्थिति इस प्रकार है :–

| पैरामीटर | औसत श्रेणीकरण | निष्कर्ष | मूल घटक |
|---|---|---|---|
| अम्लता (पीएच) | 5.80–6.40 | सामान्य रूप से अम्लीय | वन कटाई और जैविक तत्वों का अभाव |
| विद्युत सुचालकता (ईसी) | 0.10–0.45 | सामान्य | मृदा में सामान्य लवणता |
| जैविक कार्बन (ओसी) | 0.20–0.45 | अल्प | अधिकांशतः वन–कटाई और मृदा अपक्षरण के कारण |
| नाइट्रोजन (एन) | 130–260 | अल्प | अधिक उपयोग (हाइब्रिड प्रकारों) के कारण नाइट्रोजन का समाप्त होना और फसल चक्रीकरण का अभाव |
| फास्फोरस (पी) | 10–26 | मध्यम | मिट्टी का बह जाना |
| पोटाशियम (के) | 205–340 | मध्यम | मिट्टी का बह जाना और अपक्षरण |
| जिंक (जेडएन) | 0.2–0.3 | अल्प | स्थूल पोषक तत्वों के बजाय सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता |
| तांबा (सीयू) | 0.1 | अल्प | |
| बोरोन (बी) | 0.2–0.4 | अल्प | |



## 2. Impact of the Scheme in the District

The district has taken major initiatives to address the issues identified from the soil health analysis in the district. The district average soil status is as follows:

| Parameters | Average Rating | Inferences | Underlying Factors |
|---|---|---|---|
| Acidity (pH) | 5.80 – 6.40 | Moderately Acidic | Deforestation & Lack of organic content |
| Electrical Conductivity (EC) | 0.10 – 0.45 | Normal | Soil has normal salinity |
| Organic Carbon (OC) | 0.20 – 0.45 | Low | Mostly due to deforestation and soil erosion |
| Nitrogen (N) | 130 – 260 | Low | Exhaustion of Nitrogen due to over-utilization (hybrid varieties) and lack of crop rotation |
| Phosphorus (P) | 10 – 26 | Medium | Soil run off |
| Potassium (K) | 205 – 340 | Medium | Soil run off and erosion |
| Zinc (Zn) | 0.2 – 0.3 | Low | Greater requirement of micro-nutrients instead of macro-nutrients |
| Copper (Cu) | 0.1 | Low | |
| Boron (B) | 0.2 – 0.4 | Low | |

मृदा स्वास्थ्य कार्ड रिपोर्ट से पहचाने गए मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित पहल किए गए हैं :–

वन–कटाई और अत्यधिक मृदा अपक्षरण के कारण अत्यल्प जैविक कार्बन । पहचाने गए समस्या के आधार पर, एकीकृत योजना के जरिए मनरेगा (एमजीएनआईजीए) के तहत पहाड़ी से घाटी की ओर आधारित जल और मृदा संरक्षण कार्य किए गए । विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में विशेष वनरोपण अभियान चलाए गए । मृदा अपक्षरण को रोकने के लिए खेत में मेड़ कार्य भी किए गए । वन क्षेत्र में सुधार करने के लिए मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) के तहत 3680 हे. से अधिक क्षेत्र में 3345 पौधारोपण कार्य करके 12,15,800 पौधों का रोपण किया गया । इसके अतिरिक्त मृदा अपक्षरण को रोकने के लिए लगभग 4612 किसानों के 3230 हे. भूमि पर खेत में मेड़ कार्य किया गया ।

रसायनिक खादों के बहुत अधिक प्रयोग के मुद्दे का समाधान स्वयं सहायता समूह के जरिए जैविक खेती शुरू करके की गई । जिले में व्यापक स्तर पर दलहन की खेती और फसल चक्रीकरण की भी शुरूआत की गई । परम्परागत विविधताओं को बढ़ावा देने और बेहतर बाजार संपर्क बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (ईपीओ) को प्रोत्साहित करने की भी पहल की गई ।

संकर प्रजातियों के कारण अत्यल्प नाइट्रोजन तत्व की समस्या का समाधान सब्जियों और दालों की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देकर किया गया । पौध विविधता संरक्षण (पीपीवी) और किसान अधिकार प्राधिकरण (एफआरए) के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु 80 से अधिक अनाजों, दालों, सब्जियों की परम्परागत प्रजातियाँ पंजीकरण हेतु भेजी गई । इसके अतिरिक्त सुगंधित चावलों की सामूहिक खेती करने और विपणन करने हेतु 1100 किसानों के एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया । स्वयं सहातया समूह को धान की परम्परागत प्रजाति जैसे कि जीराफूल की खेती करने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया जा रहा है तथा प्रसंस्करण और विपणन करने हेतु लघु धान मिल उपलब्ध कराए गए हैं ।



The following initiatives have been taken to address the issues identified from the Soil Health Card Report:

Low Organic Carbon due to deforestation and heavy soil erosion. Based on the problem identified, Water & Soil Conservation works based on Ridge-to-Valley approach under MGNREGA were taken up through integrated planning. Special afforestation drives, especially in degraded areas have been taken up. Farm bonding works have also been taken up to check soil erosion. To improve the forest cover, 3345 Plantation works over 3680 ha with more than 12,15,800 plants have been taken up under MGNREGA. Moreover, farm bonding has been carried out on lands of about 4612 farmers on 3230 ha to check soil erosion.

Excessive use of chemical fertilizers has been addressed by introducing organic farming through Self Help Groups. Cultivation of pulses and crop rotation is also being introduced on a large scale in the district. An initiative to promote Farmer Producers' Organization (FPO) has also been taken up to promote traditional varieties and create better market linkages.

Low Nitrogen content issues because of hybrid varieties have been addressed by promoting local varieties of vegetables and pulses. More than 80 traditional varieties of cereals, pulses, vegetables sent for registration under Protection of Plant Varieties (PPV) and Farmers' Rights Authority (FRA). Besides this, a Farmer Producer Organization for collective cultivation and marketing of scented varieties of rice is formed with 1100 farmers. SHGs are being trained and motivated to cultivate traditional varieties of rice like Jeeraphool and have been provided with mini rice mills for processing and marketing.

# समूह – पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्य
# श्रेष्ठ जिला – हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

## 1. जिले में स्कीम के अंतर्गत किए गए अनुकरणीय कार्य

इस स्कीम के शुरू होने के एक वर्ष के भीतर हमीरपुर जिले के 100% मिट्टी के नमूने संग्रहित किए गए । जिले के फील्ड पदाधिकारियों – कृषि विकास अधिकारी (एडीओ), कृषि विस्तार अधिकारी (एईओ) तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमएस) के साथ साप्ताहिक बैठकों के जरिए कार्यक्रम को निकटता से मानीटर किया गया । उन्हें मिट्टी का नमूना संग्रहण करने के लिए प्रखंडवार लक्ष्य दिया गया । प्रत्येक प्रखंड के लिए दो टीमें गठित की गई ।

*जीपीएस और स्टेनलेस स्टील हाथ–बरमा क्रय करना :* कृषि निदेशालय द्वारा आवंटित छह जीपीएस और स्टेनलेस स्टील हाथ–बरमा के अलावा जिला स्तर पर सात अतिरिक्त सेटों की व्यवस्था की गई ताकि मिट्टी के नमूना संग्रहण का कार्य शीघ्रता से किया जाए ।

*किसान जागरुकता शिविरों का आयोजन :* इस स्कीम के संबंध में किसानों को अवगत कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड में तीन शिविर आयोजित किए गए ।

*फील्ड पदाधिकारियों के लिए प्रषिक्षण :* फील्ड पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय स्तर पर आयोजित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से नमूना संग्रहण में जीपीएस के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया । जिला मृदा जांच प्रयोगशालाओं का सूक्ष्म, पोषक तत्व विश्लेषण और अन्य पैरामीटरों की जांच करने हेतु सुदृढ़ीकरण किया गया । इस प्रयोजनार्थ एक अपकेंद्रण यंत्र, विद्युत सुचालकता मीटर और कैथोड लैम्प का क्रय किया गया ।

जिले ने सभी आवश्यक प्रयोगशाला संबंधी रसायन, फिल्टर कागज, कांच के उपकरणों आदि की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए । कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), मृदा संरक्षण जैसे विभाग के विभिन्न प्रभागों तथा अन्य प्रयोगशालाओं में कार्यरत स्टाफ को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संगठित किया गया ।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने और तेजी से डाटा दर्ज करने हेतु प्रयोगशाला में अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई तथा कार्ड का मुद्रण करने हेतु नए कलर प्रिंटर खरीदे गए । राज्य के उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला के कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

कृषि विभाग के विस्तारित पदाधिकारियों ने सिंचित और वर्षा सिंचित क्षेत्रों के ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने के बाद मिट्टी के मिश्रित नमूने संग्रहित किए । उन्होंने तत्संबंधी ग्रिड में आने वाले सभी खेतों के डाटा को रिकार्ड किया तथा इसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के पोर्टल पर दर्ज करने के बाद विश्लेषण करने हेतु मृदा जांच प्रयोगशाला को प्रेषित कर दिया ।



# Group – North East & Hill States
# Best-performing – District-Hamirpur, Himachal Pradesh

## 1. Exemplary Work done in the District under the Scheme

100% soil samples of the district have been collected within one year of the launch of the Scheme. The programme was closely monitored through weekly meetings with the field functionaries of the district – Agriculture Development Officers (ADOs), Agriculture Extension Officers (AEOs) and Subject Matter Specialists (SMS). They were allocated targets block-wise, for collection of soil samples. Two teams were constituted for each block.

*Procurement of GPS and Stainless Steel Augers:* In addition to the six sets of GPS and stainless steel augers allocated by the Directorate of Agriculture, seven additional sets were arranged at district level for speedy collection of soil samples.

*Organization of farmer awareness camps:* Three camps in each block were organized for sensitization of farmers about the Scheme.

*Training to the Field functionaries:* The field functionaries were trained for using GPS in sample collection through capacity building training programmes conducted at district headquarters. The District Soil Testing Laboratory has been strengthened for micro-nutrient analysis as well as for other parameters. A centrifuge, electrical conductivity meter and cathode lamps were procured for the purpose.

The district has taken all necessary measures to ensure timely procurement of all the necessary laboratory chemicals, filter papers, glassware etc. Staff working under the various divisions of the department like Agricultural Technology Management Agency (ATMA), Soil Conservation and other Labs was pooled for successful implementation of this National Program.

For generation of Soil Heath Cards and speedy data entry, additional internet connection has been arranged in the Laboratory and color printer purchased for printing cards. Five days of training for the laboratory staff was organized at State University of Horticulture & Forestry.

The extension functionaries of the Department of Agriculture collected composite soil samples after delineating the grids of irrigated and rain-fed areas. They recorded the data of all the farms falling in that grid and dispatched samples to the soil testing laboratory for analysis, after registering it on the portal of Soil Health Card.

जिले ने यह सुनिश्चित किया कि समय पर मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया जाए तथा एसएचसी पोर्टल का उपयोग करते हुए किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाए । उक्त ग्रिड के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए। स्थानीय कृषि अधिकारी ने उन्हें उनकी मृदा की स्थिति तथा फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। प्रयोगशाला के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए नमूने का विश्लेषण करने हेतु स्टाफ को देर तक, छुट्टी वाले दिनों तथा पाली ड्यूटी में नियोजित किया गया ।

## 2. किसानों के लिए लाभ

किसानों स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध उत्पादों का उत्पादन करने हेतु मृदा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पौधों के लिए पोषक तत्वों के संतुलित और तर्कसंगत प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्य और आस–पास के परिवेश पर रसायनिक खादों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के प्रति रुचि दिखा रहे हैं ।

खाद के न्यायसंगत उपयोग से फसलों का उत्पादन बेहतर हो रहा है । रसायनिक खाद संबंधी व्यय कम होने से फसलों की उत्पादन लागत में भी उल्लेखनीय कमी आ रही है ।

## 3. जिले में स्कीम का प्रभाव

जिले के किसान मृदा जांच कार्यक्रम, कृषि में इसकी महत्ता के बारे में अवगत हुए तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित प्रमुख और गौण पोषक तत्वों के संबंध में अवगत हैं। अब किसान अपनी मिट्टी की उर्वरता स्थिति सहित इसके स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु यदि किसी प्रकार के मृदा परिशोधन आवश्यक हो, के बारे में भी अवगत हैं ।

स्कीम के प्रभाव के संबंध में किसानों के साथ किए गए विचार–विमर्श अत्यंत उत्साहवर्धक रहे हैं । उन्होंने इन सिफारिशों के प्रति काफी रुचि दिखाई है और इन सिफारिशों को उत्साहपूर्वक अपना रहे हैं । अब किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किए गए सिफारिशों के अनुसार खादों के संतुलित और तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं । उन्होंने यह सहमति व्यक्त की है कि इससे उत्पादकता बढ़ी है और उनकी मृदा की उर्वरता बनी हुई है ।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वजह से पौधों के लिए पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों जैसे कि जैव–खाद, जैविक खाद, केंचुआ खाद, नीम लेपित यूरिया (नाइट्रोजन के धीमे निर्गमन के लिए) की मांग में हो रही है जिसके फलस्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा ।



The district has ensured analysis of the soil samples in time and generated the Soil Health Cards of the farmers using the SHC portal. Farmers of the grid have been given Soil Health Cards. The local agriculture officer educated them about the soil status of their fields and the requirements of nutrients for the crops. Staff was engaged for sample analysis till late hours, holidays and shift duties were assigned for maximum utilization of the lab resources.

## 2. Benefits to the Farmers

Farmers are showing interest regarding balanced and judicious use of plant nutrients keeping in view the importance of soil health in production of healthy and clean produce and to reduce the hazardous effect of chemical fertilizers on human health and the surrounding environment.

Judicious use of fertilizer is improving the production of crops. Also, with reduced expenditure on chemical fertilizers, cost of production of crops is reducing significantly.

## 3. Impact of the Scheme in the District

Farmers of the district are now aware of Soil Testing programme, its importance in agriculture for obtaining status of micro-nutrients, along with major and secondary nutrients. Farmers are also aware of fertility status of their soil, along with soil amendments needed for sustaining its health.

Interactions with farmers on the impact of the Scheme have been quite encouraging. They have shown tremendous interest and enthusiastically adopted the recommendations. Farmers are now concentrating on balanced and judicious use of fertilizers as per the recommendations in the Soil Health Cards. They agree that it increases the productivity and maintains fertility of their soil.

With SHC, the demand for organic sources of plant nutrients like bio-fertilizers, organic manures, vermin-compost, Neem coated urea (for slow release of nitrogenous fertilizer) is increasing, in turn improving the quality of soil.